Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

07 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. भारत ने हैदराबाद में INC-WMC सम्मेलन की मेजबानी की और टिकाऊ खनन के लिए तांबा और एल्युमीनियम विजन दस्तावेज और 'मिशन ग्रीन' का शुभारंभ किया।

4 जुलाई, 2025 को, विश्व खनन कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय समिति (INC-WMC) ने हैदराबाद, तेलंगाना में 'सर्वश्रेष्ठ खनन बंद करने की प्रथाओं के माध्यम से सतत और जिम्मेदार खनन' पर अपने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन किया। इस कार्यक्रम में भारत में सतत खनन को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख नीति दस्तावेजों और रूपरेखाओं का अनावरण किया गया।

• सम्मेलन में नीति निर्माताओं, पर्यावरण विशेषज्ञों, उद्योग जगत के नेताओं और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों को खदान बंद करने से संबंधित विचारों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक साथ लाया गया। मुख्य विषयों में पर्यावरणीय स्थिरता, खनन सुरक्षा, वैज्ञानिक बहाली और जिम्मेदार बंद करने के तंत्र का विकास शामिल था।

• कार्यक्रम के दौरान, "मिशन ग्रीन" पुस्तिका का विमोचन किया गया, जिसमें खदान बंद करने के मामले में भारत के सर्वोत्तम तरीकों पर प्रकाश डाला गया। यह क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और खनन की गई भूमि को कृषि, मत्स्य पालन या अन्य स्थायी उपयोगों जैसे सामुदायिक लाभों के लिए पुनः उपयोग में लाने पर केंद्रित है, जो स्थानीय आजीविका और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं।

• केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कॉपर विज़न डॉक्यूमेंट लॉन्च किया, जिसमें कॉपर को भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज के रूप में परिभाषित किया गया है। दस्तावेज़ में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचे में कॉपर की भूमिका को रेखांकित किया गया है, और इसे भारत के हरित ऊर्जा संक्रमण रोडमैप के केंद्र में रखा गया है।

Key Points:-

(i) मंत्री ने एल्युमीनियम विज़न दस्तावेज़ का भी अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारत की घरेलू आवश्यकताओं के लिए एल्युमीनियम उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। दस्तावेज़ में स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बुनियादी ढाँचे में एल्युमीनियम की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक रणनीतिक रोडमैप शामिल है, जो इसे भारत की औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन रणनीति का केंद्र बनाता है।

(ii) सम्मेलन में वैज्ञानिक खदान बंद करने के तरीकों को मजबूत करने के लिए रिक्लेम फ्रेमवर्क - रीच आउट, एनविज़न, को-डिज़ाइन, लोकलाइज़, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन - पेश किया गया। यह 6R दर्शन के अनुरूप है: पुनर्ग्रहण, पुनर्उद्देश्यीकरण, पुनर्वास, पुनःवनस्पतिकरण, उपचार और त्याग, संरचित और चरणबद्ध खदान बंद करने के संचालन को बढ़ावा देता है।

(iii) सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण तकनीकी अपडेट सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (SWCS) - एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल की शुरुआत थी, जिसे खदान बंद करने की मंजूरी को डिजिटल बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। इस मॉड्यूल का उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को

सुव्यवस्थित करना और बंद करने की योजनाओं के तेज़ और अधिक कुशल कार्यान्वयन को सक्षम बनाना है।

2. हिमाचल प्रदेश राशन वितरण के लिए आधार-आधारित फेस ID का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया।

5 जुलाई, 2025 को हिमाचल प्रदेश ने अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिए आधार से जुड़े चेहरे के प्रमाणीकरण (FaceAuth) की शुरुआत की, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग (DDTG) द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य सत्यापन संबंधी बाधाओं को दूर करना और सब्सिडी वाले खाद्यान्न की तेज़, अधिक सटीक डिलीवरी सुनिश्चित करना है।

• हिमाचल प्रदेश के मंत्रिस्तरीय सलाहकार और अधिकारी शिमला में नए FaceAuth सिस्टम का अनावरण करने के लिए एकत्रित हुए, जिससे राशन वितरण में एक बड़ा तकनीकी बदलाव आया। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (नवाचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन) गोकुल बुटेल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह कदम अविश्वसनीय OTP (वन-टाइम पासवर्ड) और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक विधियों की जगह लेगा, जो अक्सर खराब SMS डिलीवरी या UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) बेमेल के कारण विफल हो जाते थे।

• DDTG द्वारा विकसित यह प्रणाली उचित मूल्य की दुकान (FPS) डीलर के स्मार्टफोन पर स्थापित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करती है। लाभार्थी का प्रमाणीकरण अब मोबाइल कैमरे के माध्यम से होता है, जो उनके आधार से जुड़ी तस्वीर की तुलना में उनके चेहरे का लाइव स्कैन कैप्चर करता है - इस प्रकार POS (पॉइंट ऑफ सेल) प्रमाणीकरण के दौरान इंटरनेट या फिंगरप्रिंट स्कैनर पर निर्भरता को खत्म कर देता है।

• सरकारी बयानों के अनुसार, इस FaceAuth तंत्र ने प्रमाणीकरण की सफलता दर में उल्लेखनीय वृद्धि की है, सत्यापन समय को कम किया है, और FPS आउटलेट्स पर कतारों को कम किया है। गोकुल बुटेल ने इस बात पर जोर दिया कि ये सुधार हिमाचल प्रदेश की आवश्यक कल्याण सेवाओं को अधिक समान रूप से वितरित करने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं।

Key Points:-

(i) हिमाचल प्रदेश में सभी PDS राशन दुकानों में तेजी से रोलआउट मुख्यमंत्री सुखू के नेतृत्व में हुआ, जिनके प्रशासन ने पारदर्शिता, दक्षता और सामाजिक समावेशन को बढ़ाने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस पहल को प्राथमिकता दी है। यह बदलाव लंबे समय से चली आ रही सार्वजनिक सेवा चुनौतियों के लिए आधुनिक समाधान अपनाने के लिए राज्य की तत्परता को दर्शाता है।

(ii) भारत ने 2015 के आसपास PDS में आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू किया ताकि फर्जी लाभार्थियों को खत्म किया जा सके, लेकिन फिंगरप्रिंट मिसमैच और एसएमएस विफलता जैसी समस्याएं जारी रहीं। नई FaceAuth प्रणाली का उद्देश्य इन समस्याओं को अधिक विश्वसनीय और

समावेशी तकनीक के साथ हल करना है।

(iii) विशेषज्ञों का सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश में इसकी सफल तैनाती देश भर में अपनाए जाने के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है। राज्य सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और UIDAI सहित केंद्रीय निकायों से आग्रह किया है कि वे FaceAuth को अन्य राज्यों में भी लागू करने पर विचार करें। उनका तर्क है कि तकनीक आधारित रोलआउट से भारत के उन लक्ष्यों को बल मिलेगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रमाणीकरण विफलताओं के कारण कोई भी पात्र नागरिक खाद्य सहायता से वंचित न रहे।

3. बिहार ने कौशल विकास और इंटर्नशिप के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा' योजना शुरू की

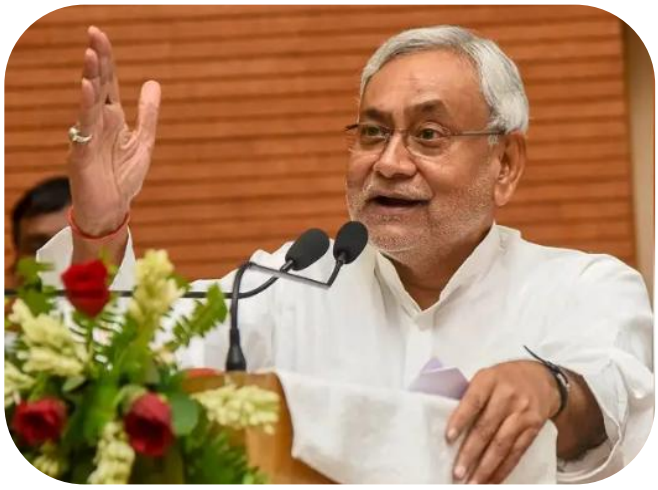

जुलाई 2025 में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 'मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा' योजना शुरू की, जिसे औपचारिक रूप से सीएम-प्रतिज्ञा (मुख्यमंत्री - युवा उन्नति के मार्गदर्शन हेतु तत्परता, जागरूकता और तकनीकी अंतर्दृष्टि का संवर्धन) के नाम से जाना जाता है। सात निश्चय-2 (सात निश्चय भाग 2) एजेंडा के तहत यह पहल 2025-26 से 2030-31 तक इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवा सशक्तीकरण पर केंद्रित है।

• इस योजना का लक्ष्य 6 साल की अवधि में बिहार भर में 1 लाख युवाओं को शामिल करना है, जिसमें 2025-26 के पहले वर्ष में 5,000 युवाओं के पायलट बैच को सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण और इंटर्नशिप में संरचित वजीफा-आधारित जुड़ाव के साथ राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता, नौकरी के लिए तत्परता और तकनीकी क्षमताओं में सुधार करना है।

• 18 से 28 वर्ष की आयु के योग्य उम्मीदवारों को कौशल विकास या इंटर्नशिप प्रशिक्षण के दौरान मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इंटर्नशिप की अवधि 3 से 12 महीने के बीच होती है, जो युवाओं द्वारा किए गए कोर्स या प्रशिक्षण मॉड्यूल पर निर्भर करती है।

Key Points:-

(i) वित्तीय सहायता मॉडल के तहत, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और कौशल प्रशिक्षण में लगे युवाओं को ₹4,000 प्रति माह मिलेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) से प्रमाणपत्र या डिप्लोमा योग्यता रखने वालों को ₹5,000 मासिक मिलेंगे, जबकि इंटर्नशिप में लगे स्नातक या स्नातकोत्तर छात्रों को ₹6,000 प्रति माह मिलेंगे।

(ii) स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, अपने गृह जिलों में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को प्रति माह अतिरिक्त ₹2,000 मिलेंगे, जबकि अपने जिलों के बाहर इंटर्नशिप करने वालों को प्रति माह अतिरिक्त ₹5,000 मिलेंगे, जिससे यह योजना अधिक समावेशी और गतिशीलता-अनुकूल बन जाएगी।

(iii) बिहार कैबिनेट ने अन्य सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहायता योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना (10 साल से अधिक के अनुभव वाले पारंपरिक कलाकारों के लिए 3,000 रुपये प्रति माह), मुख्यमंत्री गुरु-शिष्य परंपरा योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष को भी मंजूरी दे दी, जो पंचायती राज संस्थानों में चिकित्सा आपात स्थिति को

वित्तपोषित करती है।

4. राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना' शुरू की।

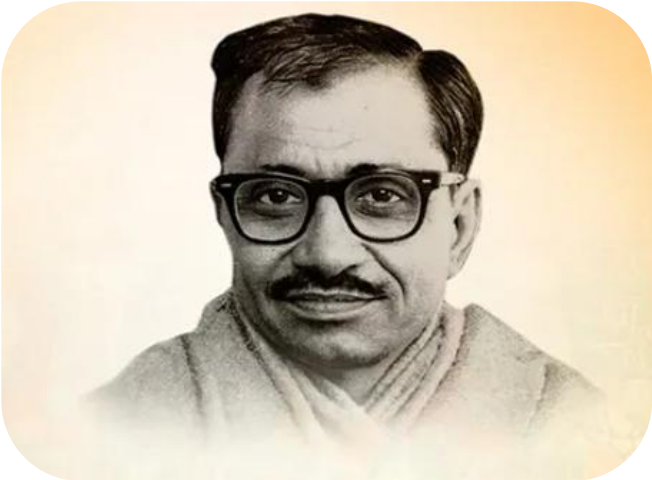

2 जुलाई, 2025 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू करने की घोषणा की। यह एक प्रमुख ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसके तहत पहले चरण में 5,000 गांवों को लक्षित किया जाएगा, जिसके लिए 1,300 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध होगी, जिसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) 30,631 परिवारों का उत्थान करना है।

- **नई योजना में प्रत्येक परिवार को ₹21,000 की नकद प्रोत्साहन राशि आवंटित की जाती है जो स्व-प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाता है। इसमें प्रत्यक्ष लाभ घटक भी शामिल हैं, जैसे स्व-रोज़गार के लिए ₹1 लाख तक की राशि, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए ₹15,000 की कार्यशील पूंजी, और वित्तीय समावेशन एवं आजीविका पहलों के लिए अतिरिक्त सहायता।**

- **5,002 गाँवों में 30,631 BPL परिवारों का व्यापक सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए 22,400 परिवारों में से 17,891 का सत्यापन किया है और निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर परिवार कार्ड जारी किए हैं।**

Key Points:-

(i) पारदर्शिता और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए, ज़िला-स्तरीय रैंकिंग शुरू की गई है: शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ज़िलों को तिमाही पुरस्कारों में ₹50 लाख, ₹35 लाख और ₹25 लाख मिलेंगे। अन्य राज्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाते हुए, ऑनलाइन गरीबी-मुक्त ग्राम कार्य योजनाओं के माध्यम से गाँवों को सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) यह पहल 24 जून, 2025 को शुरू हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा अभियान का पूरक है, जो गरीबी मुक्त परिणाम सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिकार, एनएफएसए शिकायत निवारण, स्वामित्व विलेख, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और आधार अद्यतन सहित कल्याण के अंतिम-मील वितरण पर केंद्रित है।

(iii) मुख्यमंत्री शर्मा ने एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार किया है, जिसका लक्ष्य मार्च 2027 तक 15,000 गाँवों को गरीबी मुक्त बनाना है, और दूसरे चरण में 10,000 अतिरिक्त गाँवों को शामिल किया जाएगा। यह योजना एक व्यापक ग्रामीण विकास रणनीति का हिस्सा है, जिसमें PMAY-G आवास, स्मार्ट सिटी विस्तार और 26,000 सरकारी नौकरियाँ सृजित करना शामिल है।

INTERNATIONAL

1. एलन मस्क ने अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए 'अमेरिका पार्टी' की शुरुआत की।

5 जुलाई 2025 को, अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से अमेरिका पार्टी के गठन की घोषणा की, और इसे अमेरिकी राजनीतिक खर्च पर बढ़ती निराशा के जवाब में पारंपरिक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के लिए एक राजकोषीय रूप से रूढ़िवादी, तकनीक-केंद्रित मध्यमार्गी विकल्प के रूप में पेश किया।

- **अमेरिका पार्टी की शुरुआत करने के बाद से, मस्क ने एक लक्षित रणनीति की रूपरेखा तैयार की है, जो 2-3 प्रमुख सीनेट सीटों और 8-10 हाउस जिलों को पलटने पर केंद्रित है, संघीय कानून को प्रभावित करने के लिए बहुत कम बहुमत का लाभ उठाते हुए - विशेष रूप से घाटे में कमी और नौकरशाही दक्षता जैसे क्षेत्रों में।**

- **मस्क की घोषणा 4 जुलाई को आयोजित एक सर्वेक्षण के बाद हुई, जहां एक्स पर उनके दर्शकों ने 2-से-1 के अंतर से एक नई पार्टी के गठन का समर्थन किया (लगभग 65% हां बनाम 35% नहीं), जिसे मस्क ने "आपको आपकी स्वतंत्रता वापस देने" के जनादेश के रूप में उद्धृत किया।**

- **वैचारिक रूप से, अमेरिका पार्टी को वित्तीय रूप से रूढ़िवादी, प्रौद्योगिकी समर्थक, विनियमन-विरोधी, उच्च-कुशल आव्रजन समर्थक, तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ सेना के आधुनिकीकरण का समर्थक बताया गया है, साथ ही यह जन्म-विरोधी नीतियों और मुक्त भाषण को भी बढ़ावा देती है।**

Key Points:-

(i) प्रचार के बावजूद, मस्क ने अभी तक कोई आधिकारिक कानूनी कदम नहीं उठाया है: कोई संघीय चुनाव आयोग (FEC) कागज़ी कार्रवाई दायर नहीं की गई है, कोई राज्य-स्तरीय मतपत्र पहुँच याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है, और कोई नेतृत्व दल या उम्मीदवार सूची मौजूद नहीं है। आलोचक राष्ट्रीय पार्टी को पंजीकृत करने की कठिन बाधाओं की ओर इशारा करते हैं - यहाँ तक कि अच्छी तरह से वित्तपोषित अमेरिका पार्टी को भी कई वर्षों की जटिल राज्य-दर-राज्य योग्यता प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है।

(ii) इस पहल को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डेसेंटिस ने चेतावनी दी है कि तीसरे पक्ष के प्रयास से रूढ़िवादी वोटों को विभाजित करके डेमोक्रेट्स को सत्ता सौंपने का जोखिम है। इस बीच, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के अध्यक्ष केन मार्टिन ने मस्क की वित्तीय क्षमता और सार्वजनिक असंतोष को स्वीकार करते हुए कहा कि "दोनों दलों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए"।

(iii) और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रतिक्रिया कठोर थी - उन्होंने अमेरिका पार्टी के लॉन्च को "हास्यास्पद" करार दिया, तीसरे पक्ष के इतिहास के कारण अराजकता की भविष्यवाणी की, और मस्क पर "पटरी से उतरने" का आरोप लगाया। ट्रेजरी सचिव सहित व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने संभावित वित्तीय बाजार और शासन प्रभावों का हवाला देते हुए मस्क को राजनीति से दूर रहने की चेतावनी दी है।

2. जेनिफर गीरलिंग्स-साइमन्स ने आर्थिक उतार-चढ़ाव के बीच सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

6 जुलाई, 2025 को सूरीनाम की नेशनल असेंबली ने 71 वर्षीय फिजीशियन और लंबे समय से सांसद जेनिफर गेर्लिंग्स-साइमन्स को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (NDP) का प्रतिनिधित्व करते हुए, उनका कार्यकाल - जो 16 जुलाई से शुरू होने वाला है - बढ़ती आर्थिक चुनौतियों और तेल उछाल के वादे के समय में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत देता है।

• डॉ. गीरलिंग्स-साइमन्स, जिन्होंने 25 मई, 2025 के संसदीय चुनावों में NDP को 51 में से 18 विधायी सीटें जीतने में मदद की, ने दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता वाले अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से अपना राष्ट्रपति पद सुरक्षित किया। 34 सीटों की सीमा को पूरा करने के लिए पांच अन्य दलों के साथ एक त्वरित गठबंधन बनाया गया, जिसने राष्ट्रपति चंद्रिकाप्रसाद संतोखी की प्रगतिशील सुधार पार्टी के 17 सीटों के बहुमत को समाप्त कर दिया।

• उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ, संसद में उनका कोई विरोध नहीं हुआ। गेर्लिंग्स-साइमन्स, जिन्होंने नेशनल असेंबली (2010-2020) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और जुलाई 2024 में NDP नेता बनीं, ने युवाओं और वंचित समुदायों पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लेते हुए "हमारे धन को हमारे सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए अपने सभी ज्ञान, शक्ति और अंतर्दृष्टि का उपयोग करने" की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

Key Points:-

(i) सूरीनाम की अर्थव्यवस्था अभी भी नाजुक बनी हुई है: इसने IMF समर्थित ऋण पुनर्गठन और सब्सिडी में कटौती की है, जिससे सार्वजनिक अशांति पैदा हुई है। देश को वर्तमान में ग्रैन मोर्गु अपतटीय क्षेत्रों से 2028 में तेल राजस्व प्राप्त होने से पहले सालाना लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर चुकाने होंगे।

(ii) गीर्लिंग्स-साइमन्स ने कर सुधारों को - विशेष रूप से छोटे पैमाने पर सोने के खनन में - और सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने को अपनी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं के रूप में पहचाना है।

(iii) अपतटीय क्षेत्र में तेल के बड़े भंडार की खोज - जिसका अनुमान 760 मिलियन बैरल है, तथा संभावित उत्पादन 220,000 बैरल/दिन है - ने सूरीनाम को संभावित आर्थिक परिवर्तन के लिए तैयार कर दिया है, जो तेल उत्पादन शुरू होने के बाद पास के गुयाना के 43% GDP उछाल के बराबर है। फिर भी, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि इस संभावना को साकार करने के लिए पारदर्शी शासन और तेल संपदा के समान वितरण की आवश्यकता होगी, जिसे गेर्लिंग्स-साइमन्स प्राथमिकता देना चाहते हैं।

BANKING & FINANCE

1. LIC ने युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए दो नई नॉन-लिंक्ड योजनाएं शुरू कीं: नव जीवन श्री और नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम।

जुलाई 2025 में, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने दो नए व्यक्तिगत बीमा उत्पाद लॉन्च किए- नव जीवन श्री (प्लान 912) और नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम (प्लान 911)। बचत बढ़ाने और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, इन योजनाओं को मुंबई, महाराष्ट्र में LIC के MD और CEO सत पाल भानु के नेतृत्व में लॉन्च किया गया।

• LIC के नए पेश किए गए उत्पादों को गैर-भागीदारी, गैर-लिंक्ड व्यक्तिगत योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो बचत संचय और जीवन बीमा का संयोजन प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। यह पहल युवा पीढ़ी को आकर्षित करने और विभिन्न जीवन चरणों में व्यक्तियों के लिए उपयुक्त लचीले वित्तीय सुरक्षा उत्पाद प्रदान करने के LIC के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है।

• नव जीवन श्री (प्लान 912) पॉलिसीधारकों को शिक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सुरक्षा जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कवरेज और परिपक्वता लाभों के साथ एक नियमित प्रीमियम योजना है। इस बीच, नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम (प्लान 911) एक बार भुगतान वाली पॉलिसी है जो उन व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन की गई है जो आवर्ती भुगतान के बिना एक वित्तीय कोष बनाना और सुरक्षित जीवन कवरेज पसंद करते हैं।

• इस लॉन्च के हिस्से के रूप में, LIC ने एक नया वैकल्पिक फीचर भी पेश किया है - क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर, एक नॉन-लिंक्ड हेल्थ राइडर जिसे पात्र योजनाओं के साथ एकीकृत किया जा सकता है। यह निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के निदान पर एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो नई बीमा पेशकशों के सुरक्षा पहलू को बढ़ाता है।

Key Points:-

(i) दोनों योजनाओं के लिए, प्रवेश की न्यूनतम आयु 30 दिन (पूरी हो चुकी है) और अधिकतम आयु 60 वर्ष है। परिपक्वता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष (पूरी हो चुकी है) है, और अधिकतम स्वीकार्य परिपक्वता आयु 75 वर्ष है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये योजनाएँ युवा प्रवेशकों और मध्यम आयु वर्ग के पॉलिसीधारकों दोनों के लिए हैं।

(ii) इस लॉन्च की औपचारिक देखरेख LIC के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक (MD) (प्रभारी) सत पाल भानु ने की। इस कार्यक्रम में एलआईसी द्वारा अभिनव बीमा उत्पादों के माध्यम से भारत की युवा और कामकाजी वर्ग की गतिशील जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जा रहे परिवर्तन पर जोर दिया गया।

(iii) भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), जिसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बनी हुई है, जो सभी जनसांख्यिकी के लिए वित्तीय सुरक्षा, कॉर्पस निर्माण और समावेशी कवरेज विकल्पों को संतुलित करने के लिए लगातार अपनी पेशकश विकसित कर रही है।

2. RBI की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ₹6,099 करोड़ मूल्य के ₹2,000 के नोट अभी भी प्रचलन में हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा 30 जून, 2025 को जारी किए गए नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, ₹6,099 करोड़ मूल्य के ₹2,000 मूल्यवर्ग के नोट अभी भी अर्थव्यवस्था में प्रचलन में हैं। यह शेष राशि ₹2,000 के नोटों के कुल मूल्य का सिर्फ़ 1.71% है, जो RBI द्वारा 19 मई, 2023 को उनके वापस लिए जाने की घोषणा के समय प्रचलन में थे।

- **RBI ने यह भी पुष्टि की है कि जारी किए गए कुल 2,000 रुपये के नोटों में से 98.29% - जिनकी कीमत लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपये है - पहले ही बैंकों और अन्य आधिकारिक चैनलों के माध्यम से जनता द्वारा वापस कर दिए गए हैं।**

- **19 मई, 2023 को इन्हें वापस लिए जाने के बावजूद ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। RBI ने 7 अक्टूबर, 2023 तक बैंक शाखाओं में जमा या विनिमय की अनुमति दी है और अपने 19 निर्गम कार्यालयों में इन्हें स्वीकार करना जारी रखा है।**

- **पहुँच को बेहतर बनाने के लिए, लोग भारतीय डाक के ज़रिए RBI दफ़्तरों को ₹2,000 के नोट भी भेज सकते हैं, जिससे राशि सीधे बैंक खातों में जमा हो जाएगी। यह सेवा दूरदराज या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को लक्षित करती है।**

Key Points:-

(i) प्रचलन में गिरावट - ₹3.56 लाख करोड़ से घटकर ₹6,099 करोड़ - उच्च मूल्य वाली मुद्रा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, मुद्रा प्रबंधन को बढ़ाने और अनुत्पादक भंडारण को हतोत्साहित करने की RBI की रणनीति को दर्शाती है।

(ii) 2,000 रुपये के नोटों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के अलावा, RBI ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 में घोषणा की है कि वह अब 2, 5 या 2,000 रुपये के बैंक नोट नहीं छापेगा, जो कम मूल्यवर्ग, डिजिटल विकल्पों और पुराने नोटों के पुनर्चक्रण जैसे पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं की ओर भारत की मुद्रा रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत देता है।

3. मशरेक GIFT सिटी में शाखा के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला UAE बैंक बन गया।

2 जुलाई, 2025 को, UAE स्थित मशरेक बैंक को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग इकाई (IBU) स्थापित करने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई - यह पहली बार है जब UAE बैंक ने इस वैश्विक वित्त केंद्र में प्रवेश किया है।

- **मशरेक का IBU 2025 की चौथी तिमाही तक लॉन्च होने की उम्मीद है, जो अंतिम विनियामक मंज़ूरी के अधीन है। बैंक ने पहले ही यूएई सेंट्रल बैंक और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिकारियों से मंज़ूरी**

प्राप्त कर ली है, और अब IFSCA से पूर्ण लाइसेंस का इंतज़ार कर रहा है।

• नई शाखा विदेशी मुद्रा ऋण, व्यापार वित्त और राजकोष तथा जोखिम प्रबंधन उत्पाद प्रदान करेगी। UAE के साथ GIFT सिटी के संरेखित समय क्षेत्र का रणनीतिक लाभ तेज़, अधिक सुविधाजनक सीमा पार सेवाओं को सक्षम बनाता है। शुरुआती परिचालनों को स्रोत पर कर कटौती (TDS) छूट का भी लाभ मिलेगा, जिससे वित्तीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धी संरचना की अनुमति मिलेगी।

• इस उपस्थिति को स्थापित करके, मशरेक भारत-यूएई वित्तीय सहयोग को मज़बूत कर रहा है। इसके समूह सीईओ अहमद अब्देलाल ने इस कदम को बैंक की "भारत और खाड़ी गलियारों के बीच नवाचार, निवेश को बढ़ावा देने और व्यापार को सुगम बनाने" की रणनीति का हिस्सा बताया।

Key Points:-

(i) GIFT सिटी में वैश्विक रुचि बढ़ रही है, जिसमें मशरेक ने नैटिक्सिस और फर्स्ट अबू धाबी बैंक जैसे अन्य विदेशी बैंकों के साथ मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है। जून 2025 तक, GIFT सिटी में 31 IBU संचालित हैं - जिनमें 14 विदेशी बैंक शामिल हैं - जो भारत के विस्तारित वित्तीय केंद्र को दर्शाता है।

(ii) यह विस्तार भारत और UAE के बीच पूंजी के बढ़ते प्रवाह को पूरा करने, भारत-UAE CEPA ढांचे, बढ़ते द्विपक्षीय निवेश और 2025 में भारत की अनुमानित 7% जीडीपी वृद्धि का लाभ उठाने के लिए मशरेक को तैयार करता है।

ECONOMY & BUSINESS

1. ट्रैक्सन रिपोर्ट: भारत 2025 की पहली छमाही में 889 मिलियन डॉलर के साथ फिनटेक स्टार्टअप फंडिंग में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है।

ट्रैक्सन की अर्ध-वार्षिक भारत फिनटेक रिपोर्ट H12025 के अनुसार, भारत के फिनटेक क्षेत्र ने 2025 की पहली छमाही में 889 मिलियन डॉलर जुटाए हैं, जिससे स्टार्टअप फंडिंग में तीसरी सर्वोच्च वैश्विक रैंकिंग हासिल हुई है - समग्र वैश्विक मंदी के बावजूद, यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से पीछे है।

• भारत की फिनटेक फंडिंग में H22024 में जुटाए गए रिकॉर्ड $1.2 बिलियन से 26% की गिरावट आई है और H12024 में $936 मिलियन से साल-दर-साल 5% की गिरावट आई है, जो निवेश के माहौल में नरमी को दर्शाता है। फिर भी, वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन फिनटेक पारिस्थितिकी प्रणालियों में देश की स्थिति कम नहीं हुई है।

• प्रारंभिक चरण की फंडिंग बढ़कर $361 मिलियन हो गई, जो कि H22024 के $329 मिलियन से 10% और H12024 के $333 मिलियन से 9% अधिक है, जो कि स्केलेबल, इनोवेशन-संचालित स्टार्टअप्स में बढ़ते निवेशक विश्वास को दर्शाता है। इसके विपरीत, सीड-स्टेज फंडिंग घटकर $91.2 मिलियन रह गई, जो पिछली छमाही से 27% और साल-दर-साल 33% कम है।

Key Points:-

(i) फिनटेक विलय और अधिग्रहण में तेज़ी आई, H12025 में 16 सौदे हुए - H12024 के 11 सौदों की

तुलना में 45% की वृद्धि। उल्लेखनीय लेन-देन में ग्रो द्वारा 150 मिलियन डॉलर में फिसडम का अधिग्रहण और इनक्रेड मनी द्वारा 35 मिलियन डॉलर में स्टॉको की खरीद शामिल है, जो उद्योग में समेकन को रेखांकित करता है।

(ii) भौगोलिक दृष्टि से, बेंगलुरु ने फिनटेक निवेश पर प्रभुत्व कायम किया, जिसने कुल निधियों का 55% आकर्षित किया, इसके बाद मुंबई ने 14% आकर्षित किया, जो भारत में क्षेत्रीय निवेश केंद्रों को उजागर करता है।

(iii) H12025 के दौरान शीर्ष निवेशकों में पीक XV पार्टनर्स, एंजेललिस्ट और लेट्सवेंचर शामिल थे। शुरुआती चरण के स्तर पर, एक्सेल, बेसेमर वेंचर पार्टनर्स और पीक XV ने राउंड का नेतृत्व किया, जबकि ब्लूम वेंचर्स ने सीड स्तर पर चमक बिखेरी। देर से चरण के निवेश में सॉफ्टबैंक विजन फंड, लेथ इन्वेस्टमेंट और सोफिना की प्रमुख भागीदारी थी।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. सुकन्या सोनोवाल को भारत की ओर से राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नियुक्त किया गया।

5 जुलाई 2025 को, IIT गुवाहाटी में बायोसाइंसेज और बायोइंजीनियरिंग में बी.टेक अंतिम वर्ष की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को 56 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत नेटवर्क (CYPAN) की कार्यकारी समिति में संचार और जनसंपर्क प्रमुख के रूप में 2025-2027 के कार्यकाल के लिए चुना गया।

- **असम के लखीमपुर जिले की 23 वर्षीय IIT गुवाहाटी की छात्रा तीन चरणों की चयन प्रक्रिया से उभरी है, जिसमें प्रारंभिक आवेदन, साक्षात्कार और नेतृत्व मूल्यांकन शामिल हैं। उनकी नियुक्ति शांति स्थापना, युवा सशक्तिकरण और अंतर्राष्ट्रीय संचार के प्रति उनके समर्पण को रेखांकित करती है।**

- **यह नियुक्ति असम और IIT गुवाहाटी दोनों के लिए गर्व का क्षण है, जो वैश्विक शांति पहलों में योगदान देने के लिए भारतीय युवाओं की तत्परता को दर्शाता है। संचार प्रमुख के रूप में, सुकन्या युवा-नेतृत्व वाली कूटनीति को आगे बढ़ाने और राष्ट्रमंडल में कम प्रतिनिधित्व वाली आवाज़ों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं।**

Key Points:-

(i) अपनी भूमिका में, सुकन्या नेटवर्क की संचार रणनीतियों का संचालन करेंगी, हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए युवा प्रयासों को बढ़ावा देंगी तथा राष्ट्रमंडल के 56 सदस्य देशों में संवाद, सम्मान और अंतर-सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देंगी।

(ii) एक सिद्ध नेता, सुकन्या ने STEMvibe - STEM for Viksit Bharat Empowerment की सह-स्थापना की, जो देश भर में 3,000 से अधिक छात्रों तक पहुँची, और इंटीग्रल कप का शुभारंभ किया, जो 2,500 से अधिक स्नातक छात्रों को शामिल करने वाली एक गणित प्रतियोगिता है।

(iii) उन्होंने IITG के टेक्नो-मैनेजमेंट फेस्ट टेक्नीच में मीडिया और ब्रांडिंग के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, ऑप्टिवर, क्यूब रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज और जेन स्ट्रीट जैसी वैश्विक फर्मों के साथ उनके सहयोग ने उनकी उम्मीदवारी में पेशेवर गहराई जोड़ी।

2. प्रियंका कक्कड़ को 2025-27 के कार्यकाल के लिए BRICS CCI महिला विंग की सह-अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

4 जुलाई 2025 को, आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को आधिकारिक तौर पर BRCS चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BRICS CCI) के भीतर महिला विंग की सह-अध्यक्ष (सह-अध्यक्ष) नियुक्त किया गया, जो वित्त वर्ष 2025-2027 तक उनके दो साल के कार्यकाल को चिह्नित करता है और आप के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का संकेत देता है।

- **BRICS CCI एक गैर-लाभकारी आर्थिक मंच है जो BRICS+ देशों—ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया—के व्यापारिक नेताओं को एकजुट करता है, ताकि युवा उद्यमिता, तकनीकी साझेदारी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। पिछले एक दशक में, BRICS CCI ने अपनी सदस्यता का विस्तार किया है, नए देश अध्याय (country chapters) खोले हैं और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण साझेदारियाँ स्थापित की हैं।**

- **नियुक्ति पत्र में प्रियंका कक्कड़ की नेतृत्व क्षमता, समावेशिता के प्रति जुनून और महिलाओं के विकास के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वह "इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एकदम उपयुक्त हैं।" उनके कर्तव्यों में रणनीतिक दिशा को आकार देना, उभरती हुई महिला व्यापार नेताओं को सलाह देना और भाग लेने वाले देशों में लैंगिक समानता की पहल को आगे बढ़ाना शामिल होगा।**

Key Points:-

(i) AAP की राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका और मीडिया तथा सार्वजनिक सहभागिता में उनकी विशेषज्ञता ने BRICS CCI के निर्णय में योगदान दिया। यह पहली बार है जब आप के किसी प्रमुख नेता को किसी प्रमुख बहुपक्षीय आर्थिक मंच पर इतना वरिष्ठ पद मिला है, जो पार्टी के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है।

(ii) "2025-2027" शब्द BRICS CCI के वित्तीय वर्षों को संदर्भित करता है, जिसके दौरान कक्कड़ अपने सह-अध्यक्षों के साथ मिलकर मंचों, नेतृत्व शिखर सम्मेलनों, क्षमता निर्माण कार्यशालाओं और नेटवर्किंग कार्यक्रमों का आयोजन करेंगी, जिनका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप, समावेशी औद्योगिक अवसरों और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देना है।

(iii) उनकी पदोन्नति से BRICS देशों में लैंगिक और आर्थिक मंचों पर भारत की आवाज़ बुलंद होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनके नेतृत्व से वैश्विक व्यापार वार्ता में भारत की महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ सकती है और यह AAP और BRICS इंडिया के प्रतिनिधिमंडल दोनों के लिए रणनीतिक जीत का संकेत हो सकता है।

3. इटरनल ने आदित्य मंगला को फूड ऑर्डरिंग एवं डिलीवरी बिजनेस का सीईओ नियुक्त किया।

6 जुलाई, 2025 को इटरनल लिमिटेड (जिसे पहले ज़ोमैटो के नाम से जाना जाता था) ने आदित्य मंगला को अपने फ़ूड डिलीवरी व्यवसाय का नया CEO नियुक्त किया। वे राकेश रंजन की जगह लेंगे, जो पिछले दो वर्षों से इस पद पर थे। आदित्य मंगला इस पद पर दो साल तक काम करेंगे।

• मार्च 2021 में इटरनल में शामिल हुए आदित्य मंगला इससे पहले फ़ूड डिलीवरी क्षेत्र में उत्पाद प्रमुख, आपूर्ति प्रमुख और ग्राहक अनुभव प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अपने नेतृत्व में, उन्होंने रेस्टोरेंट साझेदारियों को सुव्यवस्थित किया और पूरे प्लेटफ़ॉर्म पर उपयोगकर्ता संतुष्टि को बढ़ाया।

• निदेशक मंडल ने 6 जुलाई, 2025 को मंगला की नियुक्ति को मंजूरी दे दी, और स्टॉक एक्सचेंजों को आधिकारिक विनियामक फाइलिंग के माध्यम से इस बदलाव की जानकारी दी गई। पदभार ग्रहण करने के बाद, राकेश रंजन वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक समूह का हिस्सा नहीं रहे।

Key Points:-

(i) इटरनल के संस्थापक और CEO दीपिंदर गोयल ने मंगला के नेतृत्व गुणों की प्रशंसा की - उनकी "विनम्रता, व्यवस्थित सोच, निर्णायकता और चुनौती लेने की इच्छा" को अगले विकास चरण में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक गुणों के रूप में उजागर किया।

(ii) इटरनल में शामिल होने से पहले, मंगला ने स्टार्टअप्स और HCL टेक्नोलॉजीज और ब्लूमबर्ग जैसी प्रमुख फर्मों में उत्पाद, P&L, और मार्केटिंग में नेतृत्व की भूमिका निभाई थी, और उनके पास ISB से MBA, CMU से सूचना नेटवर्किंग में मास्टर और NSIT से IT की डिग्री शामिल है।

(iii) यह नेतृत्व परिवर्तन तेजी से विकास के बीच अपने मुख्य खाद्य वितरण व्यवसाय पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए इटरनल की व्यापक रणनीति के अनुरूप है; कंपनी के Q4 FY25 के परिणामों ने 64% साल-दर-साल राजस्व वृद्धि को ₹5,833 करोड़ तक दिखाया, जिसमें इसके खाद्य वितरण खंड ने कुल परिचालन आय का 35% योगदान दिया।

SPORTS

1. भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में तीन स्वर्ण सहित रिकॉर्ड 11 पदक जीते।

कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 (30 जून-7 जुलाई) में, भारत की मुक्केबाजी टीम ने 11 पदक हासिल करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया - जिसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल थे - जो मुख्य रूप से महिला वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण संभव हुआ।

• भारत ने स्वर्ण पदकों की शुरुआत तब की जब 24 वर्षीय दो बार की युवा विश्व चैंपियन साक्षी ने

महिलाओं के 54 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में अमेरिका की योसलाइन पेरेज़ को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराकर अपना दबदबा बनाया। उनके शानदार संयोजन और रिंग पर नियंत्रण ने दोपहर के खेल की दिशा तय कर दी।

• स्वर्ण पदकों की जीत जारी रही, क्योंकि पेरिस 2024 ओलंपियन जैस्मीन लेम्बोरिया ने 57 किग्रा महिला वर्ग के फाइनल में ब्राजील की जुसीलेन रोमेउ को 4-1 से हराकर जीत हासिल की, जबकि नूपुर ने कजाकिस्तान की येलदाना तालीपोवा पर 5-0 की शानदार जीत के साथ हेवीवेट महिला (+80 किग्रा) का स्वर्ण पदक जीता।

Key Points:-

(i) विश्व बॉक्सिंग कप 2025 में भारतीय मुक्केबाज़ों ने रजत पदकों की संख्या बढ़ाते हुए कुल पाँच रजत पदक अपने नाम किए। मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में दमदार प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें कजाखस्तान की नज़ीम किज़ैबाए के खिलाफ बेहद कड़े मुकाबले में 3–2 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा और वह रजत पदक तक सीमित रहीं। इसी तरह, जुगनू (85 किलोग्राम), पूजा रानी (80 किलोग्राम), हितेश गुलिया (70 किलोग्राम) और अभिनाश जम्वाल (65 किलोग्राम) ने भी अपने-अपने वर्गों में फाइनल तक का सफर तय किया। हालांकि, सभी को अनुभवी और शीर्ष अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ों से कड़ी टक्कर मिली और वे स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए, लेकिन उनका रजत पदक जीतना भारत के लिए गर्व का विषय रहा। इस प्रदर्शन ने वैश्विक मुक्केबाज़ी में भारत की बढ़ती ताकत और तकनीकी कौशल को दर्शाया।

(ii) भारत की कांस्य पदक तालिका में संजू (60 किग्रा), निखिल दुबे (75 किग्रा) और नरेंद्र बेरवाल (+90 किग्रा) शामिल थे, जो सभी सेमीफाइनल में पहुंचे लेकिन तीसरे स्थान पर नहीं पहुंच सके।

(iii) यह विजयी प्रदर्शन ब्राज़ील के फ़ोज़ डू इगुआसू में भारत के पिछले चरण की तुलना में काफ़ी बेहतर रहा, जहाँ उन्होंने छह पदक (एक स्वर्ण और एक रजत सहित) जीते थे। 31 देशों के 400 से ज़्यादा मुक्केबाज़ों के साथ, अस्ताना चरण कप के पहले वर्ष में भारत का सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन रहा।

AWARDS

1. प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक अर्जेंटीना यात्रा के दौरान 'ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी' भेंट की गई।

5-6 जुलाई, 2025 को ब्यूनस आयर्स की दो दिवसीय द्विपक्षीय यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भारत-अर्जेंटीना संबंधों को मजबूत करने के उनके प्रयासों के सम्मान में, शहर सरकार के प्रमुख जॉर्ज मैक्री द्वारा ब्यूनस आयर्स शहर की प्रतिष्ठित कुंजी से सम्मानित किया गया।

• प्रधानमंत्री मोदी 57 वर्षों में अर्जेंटीना की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस समारोह में भारतीय प्रवासियों का उत्साहपूर्ण समर्थन देखने को मिला, जो अल्वियर पैलेस होटल के बाहर एकत्र हुए, झंडे लहराए, देशभक्ति के गीत गाए और सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए, जिससे लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला गया।

• कुंजी प्राप्त करने के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की - अर्जेंटीना के मुक्तिदाता जनरल जोस डी सैन मार्टिन के स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित की, और दोनों देशों के बीच साझा मूल्यों के प्रतीक महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

Key Points:-

(i) राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ वार्ता के दौरान, मोदी और माइली ने कृषि, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और लिथियम खनन में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। उम्मीद है कि अर्जेंटीना लिथियम और शेल गैस उपलब्ध कराकर भारत के ऊर्जा परिवर्तन में सहयोग करेगा, जबकि भारत अपनी फार्मास्यूटिकल्स के लिए आसान पहुंच चाहता है।

(ii) प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए ट्वीट किया: "ब्यूनस आयर्स के शहर सरकार के प्रमुख श्री जॉर्ज मैक्री से ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ"। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह चाबी दोनों शहरों के बीच मित्रता और विश्वास का प्रतीक है।

(iii) यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की व्यापक यात्रा का हिस्सा है, जिसमें त्रिनिदाद और टोबैगो (जहां उन्हें ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक प्राप्त हुआ), ब्राजील (BRICS शिखर सम्मेलन के लिए) और नामीबिया शामिल हैं - जो वैश्विक दक्षिण के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को उजागर करता है।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. PM मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लिया और वैश्विक दक्षिण आवाज तथा बहुपक्षीय सुधारों को आगे बढ़ाया।

6-7 जुलाई, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने वैश्विक संस्थानों में सुधार, जलवायु न्याय को बढ़ावा देने, AI के जिम्मेदार उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने की पुरजोर वकालत की।

• प्रधानमंत्री मोदी ने "वैश्विक शासन में सुधार और शांति एवं सुरक्षा" विषय पर आयोजित उद्घाटन पूर्ण सत्र में भाग लिया, जहाँ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक (WB) जैसी प्रमुख बहुपक्षीय संस्थाओं में संरचनात्मक परिवर्तनों का आह्वान किया। उन्होंने वैश्विक आतंकवाद पर भी चिंता व्यक्त की और अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले का उदाहरण देते हुए कहा कि आतंकवाद-निरोध एक साझा प्राथमिकता होनी चाहिए।

• बहुपक्षीय, आर्थिक-वित्तीय मामले और AI पर सत्र में, प्रधानमंत्री मोदी ने चार प्रमुख प्रस्तावों को रेखांकित किया: BRICS देशों की दीर्घकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए विकास बैंक (NDB) को मजबूत करना; BRICS विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान भंडार बनाना; महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सहयोग बढ़ाना; और नवाचार और नैतिकता को संतुलित करने वाले जिम्मेदार एआई विकास को सुनिश्चित करना।

Key Points:-

(i) PM मोदी ने इंडोनेशिया का BRICS के नए पूर्ण सदस्य के रूप में स्वागत किया, जहाँ उसके राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो पहली बार इस पद पर उपस्थित हुए। उन्होंने वर्षावन संरक्षण प्रयासों के वित्तपोषण हेतु ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF) शुरू करने के ब्राज़ील के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित देशों से जलवायु वित्त और न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए ठोस प्रतिबद्धताओं का आह्वान किया।

(ii) शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा, क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डिआज़-कैनेल और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। चर्चाओं में व्यापार, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई, और इसमें वर्ष 2028 में COP33 (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 33वाँ सम्मेलन - UNFCCC) की मेज़बानी के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन भी शामिल था।

(iii) BRICS शिखर सम्मेलन के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ब्रासीलिया गए, जहाँ उनका औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें 114 घोड़ों की घुड़सवार सेना की सलामी और पारंपरिक सांबा-रेगे नृत्य शामिल थे। ब्राज़ील की यह यात्रा उनके पाँच देशों के व्यापक राजनयिक दौरे का हिस्सा है, जिसमें त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, नामीबिया और इंडोनेशिया की यात्राएँ भी शामिल हैं, जो वैश्विक दक्षिण में भारत के नेतृत्व को मज़बूत करती हैं।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. भारत ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा और जीनोमिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए फेनोम इंडिया 'राष्ट्रीय बायोबैंक' का उद्घाटन किया।

6 जुलाई, 2025 को, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित CSIR-IGIB में भारत का पहला राष्ट्रीय बायोबैंक—एक केंद्रीकृत जीनोमिक और स्वास्थ्य डेटाबेस—लॉन्च किया। फेनोम इंडिया परियोजना के तहत इस पहल का उद्देश्य सटीक चिकित्सा के लिए विविध जनसंख्या डेटा एकत्र करके स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाना है।

- **वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जीनोमिक्स और इंटीग्रेटिव बायोलॉजी संस्थान (CSIR-IGIB) द्वारा निर्मित राष्ट्रीय बायोबैंक, विभिन्न भौगोलिक, जातीय और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के 10,000 भारतीय प्रतिभागियों से व्यापक जीनोमिक, जीवनशैली और नैदानिक डेटा एकत्र करेगा, जो दीर्घकालिक कोहोर्ट अध्ययन के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करेगा।**

- **UK बायोबैंक से प्रेरित लेकिन भारत की विशाल विविधता के अनुरूप, यह बायोबैंक AI-संचालित निदान, जीन-निर्देशित चिकित्सा और रोगों का शीघ्र पता लगाने में सक्षम होगा। इससे मधुमेह, कैंसर, हृदय रोगों, दुर्लभ आनुवंशिक विकारों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) पर अनुसंधान में तेजी आने की उम्मीद है।**

Key Points:-

(i) लॉन्च के दौरान, डॉ. सिंह ने क्वांटम तकनीकों, क्रिस्पर-आधारित जीनोम एडिटिंग और एएमआर में

भारत के अग्रणी कार्यों में भारत की क्षमताओं पर ज़ोर दिया। उन्होंने जनसंख्या-विशिष्ट आँकड़ों का लाभ उठाकर केंद्रीय मोटापे जैसी भारत-विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के महत्व पर ज़ोर दिया।

(ii) CSIR के नेताओं, जिनमें डीजी डॉ. एन. कलैसेल्वी शामिल हैं, ने बायोबैंक को भारत को व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में "एक शिशु कदम" बताया। निदेशक डॉ. सौविक मैती ने IGIB की विरासत को उजागर किया—भारतीय जीनोम को डिकोड करना, कोविड-19 अनुक्रमण करना, 300+ दुर्लभ बीमारियों के निदान विकसित करना, और सिकल सेल एनीमिया जैसी स्थितियों के लिए चल रहे CRISPR उपचार।

2. भारत 2024 में चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन जाएगा।

भारत आधिकारिक तौर पर 2024 में दुनिया में जैव ईंधन का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है, जिसने पहली बार चीन को पीछे छोड़ दिया है। खपत में साल-दर-साल 40% की वृद्धि के साथ, भारत अब वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो ऊर्जा विविधीकरण और जलवायु लक्ष्यों पर देश की नीतिगत फोकस को दर्शाता है।

• 2024 में, भारत की जैव ईंधन खपत 77,000 बैरल तेल समतुल्य प्रति दिन (kboe/d) तक पहुंच गई, जिससे यह वैश्विक रैंकिंग में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और इंडोनेशिया से पीछे रह गया।

• अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) और रिस्टैड एनर्जी के अनुसार, वैश्विक जैव ईंधन की मांग 2.2 मिलियन बैरल/दिन थी, और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वृद्धि में अकेले भारत की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी थी, जहां सबसे अधिक क्षेत्रीय वृद्धि देखी गई।

• खपत में वृद्धि के बावजूद, भारत का जैव ईंधन उत्पादन केवल 70,000 बैरल/दिन था, जबकि चीन लगभग 1,06,000 बैरल/दिन उत्पादन करता था। इसका मतलब है कि भारत अपनी घरेलू माँग को पूरा करने के लिए आंशिक रूप से आयात या मौजूदा स्टॉक पर निर्भर है, जो उपयोग और घरेलू उत्पादन के बीच के अंतर को रेखांकित करता है। फिर भी, भारत में उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 27% बढ़ा, जो स्थिर प्रगति दर्शाता है।

Key Points:-

(i) पिछले दशक (2014-2024) में, भारत के जैव ईंधन परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जैव ईंधन की खपत 31.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) और उत्पादन 30.4% की दर से बढ़ा है, जो निरंतर नीतिगत समर्थन और निजी क्षेत्र की भागीदारी को दर्शाता है। स्वच्छ ऊर्जा और सम्मिश्रण अधिदेशों पर भारत का बढ़ता ध्यान इस वृद्धि का एक प्रमुख कारण रहा है।

(ii) भारत सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम सहित कई पहलों को लागू कर रही है, जिसका लक्ष्य 2025-26 तक 20% मिश्रण प्राप्त करना है। फीडस्टॉक स्रोतों में विविधता लाकर गन्ना, मक्का, अतिरिक्त चावल, जट्रोफा और संपीड़ित बायोगैस को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि 2025 में, सरकार ने 52 लाख टन अतिरिक्त चावल

को इथेनॉल उत्पादन के लिए पुनर्निर्देशित किया, और भारत शुद्ध मक्का आयातक भी बन गया, जिससे 2024 में इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 10 लाख टन मक्का आयात हुआ।

(iii) वैश्विक जैव ऊर्जा क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका उसके जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें पेरिस समझौते के तहत उसके अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के अनुसार, 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि नीतिगत बाधाओं को दूर करने और दूसरी पीढ़ी (2G) जैव ईंधनों को समर्थन देने से, भारत 2030 तक अपने जैव ईंधन के उपयोग को तीन गुना बढ़ा सकता है, जिससे यह वैश्विक ऊर्जा स्थिरता में एक अग्रणी शक्ति बन जाएगा।

Static GK

International Copper Association (ICA)	अध्यक्ष और CEO : जुआन इग्नासियो डियाज़	मुख्यालय : वाशिंगटन, डी.सी., USA
Himachal Pradesh	मुख्यमंत्री: सुखविंदर सिंह सुक्खू	राज्यपाल: शिव प्रताप शुक्ला
Suriname	राजधानी: पारामारिबो	आधिकारिक भाषा: डच
Life Insurance Corporation of India (LIC)	CEO & MD (प्रभारी) : सत पाल भानु	मुख्यालय: मुंबई
Tracxn Technologies	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) : नेहा सिंह	मुख्यालय : बेंगलुरु, कर्नाटक
Bihar	मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार	राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
Mashreq Bank	CEO : अहमद अब्देलाल	मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
Rajasthan	मुख्यमंत्री: भजन लाल शर्मा	राज्यपाल: हरिभाऊ बागड़े